कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा ख़िलाफ़त कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिये जाने की घोषणा से इसमें नयी ऊर्जा का संचार हो गया। इसके पश्चात् वर्ष 1921 और 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली।

चित्र: असहयोग आंदोलन

4.6 आंदोलन का प्रसार

असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन की शुरुआत **अगस्त 1920** में हुई। यह आन्दोलन अधिकतर स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया और प्रत्येक वर्ग की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया लेकिन भिन्न-भिन्न लोगों के लिए इसके भिन्न-भिन्न अर्थ थे।

4.6.1 शहरों में आंदोलन

- शहरी मध्य-वर्ग ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी की।
- हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा।
- पूरे देश में आचार्य नरेन्द्र देव, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चन्द्र बोस 'नेशनल कालेज कलकत्ता' के प्रधानाचार्य बन गये। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थानों ने इस आन्दोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभभाई पटेल, आसफ अली, टी. प्रकाशम और राजेन्द्र प्रसाद के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोतसाहित हुए।
- मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। उनके लिए काउंसिल का चुनाव एक ऐसा माध्यम था जिससे मुख्यतः ब्राह्मणों के नियंत्रण वाली सत्ता में कुछ हिस्सेदारी उनकी भी हो जाती।

VISION